

यूसीसी का मसौदा तैयारः सबको मिलेगा एक समान अधिकार

नया इतिहास रचेगी धामी सरकार: यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखण्ड



देहरादून(उद ब्यूरो)। देवभूमि उत्तराखण्ड में पहली बार समान नागरिक संहिता लागू होने से दशकों से चली आ रहीं कुरीतियाँ और कुप्रथाएं खत्म होंगी। सभी को एक समान अधिकार मिल सकेगा। बेटा-बेटी और स्त्री-पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म होगा। यह कहना है कि समान नागरिक संहिता की कानूनी जंग लड़ने वाले अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय का। सीएम आवास में यूसीसी की विशेषज्ञ समिति की ड्रापट रिपोर्ट सौंपने के दौरान उपाध्याय ने मीडिया से समान नागरिक संहिता की विशेषताओं और उनके संभावित प्रावधानों को साझा किया है। समिति ने यूसीसी का ड्रापट सौंप दिया है। सरकार ड्रापट का परीक्षण गोद लेने के लिए एक समान कानून की वकालत की। 1971 में भी वारा दोहराया। हालांकि 1977 और 1980 में इस मुदे पर कोई बात नहीं हुई। 1980 में भाजपा का गठन हुआ। भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बोने पार्टी ने 1984 में पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें केवल दो सीटें मिली। 1989 में 9वा

यूसीसी ड्राफ्ट में विवाह, तलाक और पति
पत्नी के लिए किए हैं कई बड़े प्रावधान!

दे हरादून (उद संवाददाता)। उत्तराखण्ड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रहा है। शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (सेन) रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने ड्राफ्ट रिपोर्ट स्थान पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। अब कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। जिसके बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट में कई बड़े प्रावधान किए हैं। ड्राफ्ट के संभावित प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अब लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाई जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सकें। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगेर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति-पत्नी दोनोंको तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग-अलग ग्राउंड हैं। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियोंको लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेरयर लड़की से अधिक है। नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ा माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुर्णविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कपेंशन में माता-पिता का भी हिस्सा होगा। मेंटेंस: अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा। एडॉप्शन: सभी को मिलेगा गोद लेने का अधिकार। मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। हलाला और इहत पर रोक होगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा जिसका एक वैधानिक फॉर्मैट लग सकती है। गार्जियनशिप- बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। पति-पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पैरेंट्स को दी जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा: विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न वर्गों के सुझावों देवभूमि की जनता से चुनाव से तैयार किया गया है समान नागरिक संहिता कानून का डाफ्ट में किया था पहला वादा: धार्मी

देहरादन(उद संवाददाता)।

उत्तराखण्ड में समान नागरिक सहिता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने शुक्रवार को मुख्य सेवक सदन में ड्राफ्ट मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित सम्मेलन में प्रेस से वार्ता के दौरान यूसीसी कानून के सबध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि समिति ने विभिन्न वर्गों के सुझावों के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से किए गये वारे के अनुरूप सरकार गठन के तुरंत बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक सहित बनाने के लिए प्रक विशेषज्ञ

उत्तराखण्ड में 43 जनसंवाद कार्यक्रम में लगभग 10 हजार लोगों से संवाद एवं प्राप्त 2 लाख 33 हजार सद्वावों का अध्ययन करने हेतु समिति की 72 बैठकें हुई



सहित बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय समिति गठित की गई। यूसीसी के लिए गठित समिति में पूर्व न्यायाधीश डॉ रंजना प्रकाश, सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री प्रमोद कोहली, उत्तराखण्ड के पूर्व

मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रे. सुरेखा डंगवाल एवं समाजसेवी श्री मनु गौड़ को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति ने दो उप समितियों का गठन भी किया। जिसमें से एक उपसमिति ने संहिता का प्रारूप तयार

किया एवं दूसरी उपसमिति ने प्रदेश के निवासियों से सुझाव आमत्रित कर संवाद स्थापित किया। समिति द्वारा देश के प्रथम गांव माणा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरूआत की गई। उन्होंने बताया कि समिति ने कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रम किए। जिसमें समिति को कुल 2 लाख

32 हजार 961 सुझाव प्राप्त हुए जो कि प्रदेश के लगभग 10% परिवारों के बराबर है। लगभग 10 हजार लोगों से संवाद एवं प्राप्त लगभग 02 लाख 33 हजार सुझावों का अध्ययन करने हेतु समिति की 72 बैठकें हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट का विधिक अध्ययन और परीक्षण कर यथाशीघ्र उत्तराखण्ड राज्य के लिए समान नागरिक संहिता कानून का प्रारूप तैयार कर संबंधित विधेयक को आगामी विधानसभा के विशेष सत्र में रखेगी। इस कानून को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रत्नांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदर्मन, श्री विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव श्री पराग मधुकर धकाते, समान नागरिक संहिता के सदस्य सचिव श्री अजय मिश्रा एवं महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।



कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने बाद के मुताबिक हमनें सरकार गठन के तुरंत बाद ही पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया था और सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की। उन्होंने कहा कि इस देवभूमि से तैयार होने वाला यह विधेयक प्रदेश हित के साथ ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ तथा सबका साथ, सबका विकास के प्रधानमंत्री श्री मोदी के मूल मंत्रों को साकार करने की विश्वा में उठाया गया कदम है। यह किसी के भी विरोध के लिए नहीं लाया गया है। उत्तराखण्ड का प्रस्तावित कानून दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है।

पवन गावा ने व्यापारियों से लिया आशीर्वाद



रुद्रपुर (उद संवाददाता)। व्यापार मण्डल चुनाव में कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी पवन गावा पल्ली ने अंतिम दिन बाजार में व्यापक जनसंपर्क कर चुनाव में विजयी बनाने की अपील की। अपने समर्थकों के साथ जोर शोर से प्रचार में जुटे पवन गावा पल्ली ने दुकानों पर जाकर व्यापारियों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगह जगह पवन गावा का

व्यापारियों ने स्वागत किया और उन्हें जीत के लिए आश्वस्त किया। पवन गावा पवन गावा ने किया कि व्यापार मण्डल में उनका का पहला चुनाव है उन्होंने व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करने का प्रयास किया है। व्यापारियों की समस्याओं का निरकरण करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि

उत्तरांचल दर्पण

सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

ईडी की जांच और पूछताछ

अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रवर्तन निदेशालय के बीच जोर आजमाइश चल रही है। आबकारी नीति में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने पांचवां बार मुख्यमंत्री अरविंद केरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, मगर उन्होंने फिर यह कह कर उसे टाल दिया कि नोटिस अवैध है। चंडीगढ़ के मेरठ चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर पार्टी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसमें अरविंद केरीवाल को भेजे गए नोटिस का मुद्दा भी शामिल था। खुद केरीवाल ने इसे लेकर प्रेसवार्ता की और बताया कि किस तरह केंद्र सरकार उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। वह नहीं चाहती कि वे आम चुनाव में प्रचार करने जा सकें। उन्होंने बताया कि शराब घोटाला मामले में लंबे समय से सीबीआइ और ईडी जांच कर रही हैं, मगर उन्हें आज तक एक भी पुछता सबूत हाथ नहीं लगा है। यह पहली बार नहीं है, जब अरविंद केरीवाल और आम आदमी पार्टी इस मामले को बेबुनियाद, मनगढ़ंत और बेवजह परेशान करने की नीत से रचा गया था। तबसे लेकर अब तक उनका यही दावा है कि वे कट्टर ईमानदार लोग हैं, उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है। मगर अब प्रवर्तन निदेशालय पर शायद उनके तर्कों, शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक हथकंडों का शायद ही कोई असर पड़ा। ईडी को कानूनी अधिकार है कि तीन बार से अधिक नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोई व्यक्ति पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होता है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। यह उसके कुछ अधिकारी उसमें पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि पिछले साल अप्रैल में सीबीआइ केरीवाल से करीब नौ घंटे पूछताछ कर चुकी है। मगर ईडी से वे बचते फिर रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ऐसे ही तर्कों के साथ ईडी का सामना करने से बच रहे थे। आखिरकार अधिकारियों ने उनके कार्यालय में जाकर पूछताछ की और जब वे अपने पक्ष में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, तो दो दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केरीवाल खुद यह बात कह रहे हैं कि यही प्रक्रिया उनके साथ भी दोहराई जा सकती है। बेशक ईडी और सीबीआइ की कार्यशैली लंबे समय से प्रश्नांकित की जा रही है, पर यह सबाल अपनी जगह बना हुआ है कि अगर अरविंद केरीवाल सचमुच बेदाम हैं, उनका शराब घोटाले से कोई लेना-देना नहीं, तो फिर उन्हें ईडी के सबालों से बचने की जरूरत क्या है। उन्हें अपने पक्ष में सबूत पेश करने में हिचक क्वांटों होनी चाहिए। एक समय वे खुद कामकाज में पारदर्शित के लिए आरोपी नेताओं को कानून का सामना करने की वकालत करते थे। फिर उन्हें इस मामले में कन्नी काटने की क्या जरूरत? इस मामले में उनके दो नेता सलाहकारों को पीछे हैं। अगर सचमुच आबकारी नीति सही थी और उसके तहत शराब के ठेकों का आबंटन आदि पारदर्शी तरीके से किया गया था, तो उन्हें इसके प्रमाण पेश करके इस मामले पर से पर्दा उठाना चाहिए। इस तरह की राजनीतिक रस्साकशी से आखिरकार आम नागरिक दिव्यांगित होते हैं।

परियोजनाओं के निर्माण में इंटिग्रेटेड प्लान के साथ कार्य करने की दी कड़ी हिदायत

देहरादून (उद संवाददाता)। राज्य में परियोजनाओं के निर्माण के संदर्भ में संसाधनों के अपव्यय को समाप्त करने के दृष्टिगत मुख्य सचिव श्रीमती राधा रत्नां ने व्यव्यक्ति समिति की बैठक में संवर्धित अधिकारियों को सभी प्रोजेक्ट्स के निर्माण के दौरान इंटिग्रेटेड प्लान के साथ कार्य करने की कड़ी हिदायत दी है। मुख्य सचिव ने गोपेश्वर एवं रुद्धीकी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनेवाले 50 बेड के किंटिकल केयर ब्लॉक की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग को सख्त हिदायत दी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से वर्तमान अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने मानस्कण्ड योजना के तहत चंपावत में रेवीधूरा बारही देवी मंदिर के सैंहित्यकरण की समीक्षा करते हुए मंदिर के रिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनेवाले 50 बेड के किंटिकल केयर ब्लॉक की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग को सख्त हिदायत दी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से वर्तमान अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है। राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य महकमा विजिलेंस के रुपरेखा देवी विभागों के लिए ही सबसे अधिक शिकायतें डायल 1064 पर आ रही हैं। नीतीजतन विजिलेंस ने तीन साल के भीतर 42 ट्रैप किए जिनमें से आधे से ज्यादा इन्हीं तीनों के विभाग के हैं। सबसे ज्यादा राजस्व विभाग के 15 अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। यह जानकारी शुक्रवार को डायरेक्टर विजिलेंस डॉ. वी. मुरुगेशन ने पत्रकारवारी में दी। इस दौरान उन्होंने पिछले साल की गिरफ्तार की कार्यवाही और भविष्य की कार्यवाही जीवनकारी शुक्रवार को डायरेक्टर विजिलेंस डॉ. वी. मुरुगेशन ने बताया कि भ्रष्टाचार के एक साल में एक अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत लेते दबोचा गया है। 2021 में कुल सात अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते दबोचा गया

वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे युवाओं के सपने होंगे पूरे

शोध के लिए युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज

बीते कुछ सालों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक वैश्विक उपलब्धियां हासिल करके दुनिया को चौंकाने का काम कर दिया है। इनमें पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य-एल मिशन प्रक्षेपित करना और इसरो द्वारा ब्लैक होल के रहस्यों को खंगालने के लिए उपग्रह भेजने जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। भविष्य में भारत अंतरिक्ष में मानव युक्त गणनायन भेजने और शुक्र ग्रह पर पर जाने की तैयारी में है। धरती और असुम्री सतह पर भी उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं। बावजूद वैज्ञानिक अनुसंधानों में भारत कई दशों से पिछड़ रहा है। धन की कमी के चलते संस्थाएं और मौलिक सौचरणीय रहस्यों की बढ़ियां हैं। इसकी एक बजह निजी क्षेत्र का अनुसंधान में ज्यादा योगदान नहीं देना भी रहा है। लेकिन अब 2024 के अंतरिम बजट में ऐसे प्रावधान कर दिए हैं, जो युवाओं के सपने पूरा करने में मदद करेंगे। उन्हें अब धन की कमी आड़े नहीं आएगी। शोध के लिए वे जितना चाहेंगे, ब्याज मुक्त धन मिल जाएगा। बजट में सरकार ने युवाओं के सपने साकार करने के लिए बड़ा एलान किया है। इसके अंतर्गत 50 वर्षीय तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण हेतु एक लाख करोड़ रुपए की निधि तय की गई है, इससे उभरते नवीन क्षेत्रों में अनुसंधान और आविष्कारों के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पहल से शोध में तो जीवनांश दर्शाता विकासित करने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत भविष्य में धन की कमी हुई है। इनमें गुना ज्यादा धन शोध पर खर्च करते हैं। यदि यही सिलसिला जारी रहता तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत भविष्य में धन की हुई है। इनमें रामानुजन शोधवृत्ति, सेतु-योजना, प्रेरणा-योजना और विद्यार्थी-वैज्ञानिक धन बढ़ाकर भारत ने न केवल युवाओं के हासिलों को उडान भरने के लिए एक लॉन्ग ट्रैक की तैयारी की है। इसके अंतर्गत योजनाएं देश के लिए वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। बैंगलुरु के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) से जुड़े संस्थानों में लोगों को भूमिका लिया जाएगा। यह वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। बावजूद देश के लगभग सभी शीर्ष संस्थानों में वैज्ञानिकों की कमी है। वर्तमान में देश के 70 प्रमुख शोध - संस्थानों में 3200 वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। बैंगलुरु के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) से जुड़े संस्थानों में सबसे ज्यादा 177 पद रिक्त हैं। पुणे की राश्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में 123 वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। देश के इन संस्थानों में यह स्थिति तब है, जब सरकार ने पदों को भरने के लिए के आकर्षक योजनाएं शुरू की हुई हैं। इनमें गुना ज्यादा धन शोध पर खर्च करते हैं। यदि यही सिलसिला जारी रहता तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत भविष्य में धन की हुई है। इनमें रामानुजन शोधवृत्ति, सेतु-योजना, प्रेरणा-योजना और विद्यार्थी-वैज्ञानिक धन बढ़ाकर भारत ने न केवल युवाओं के हासिलों को उडान भरने के लिए एक लॉन्ग ट्रैक की तैयारी की है। इसके अंतर्गत योजनाएं देश के लिए वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। बैंगलुरु के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) को न तो विज्ञान सम्मत माना जाया और न ही गणपति भूमि को अशिक्षित होने के कारण केंद्र या राज्य सरकार से सम्मानित किया गया। यह व्यवहार प्रतिभा का अनादर है। यहां गौरतलब है कि 1930 में जब देश में फिरांगी हुक्मसूत्र थी, तब देश में वैज्ञानिक शोध का बुनियादी ढांचा न के बरबर था। विचारों को रचनात्मकता देने वाला साहित्य भी अपर्याप्त था। अंग्रेजी शिक्षा शुरूआती में दौर में थी। बावजूद जगदीश चंद्र बसु ने भौतिकी और जीव-विज्ञान में वैज्ञानिक एवं अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। लेकिन इस आविष्कार को न तो विज्ञान सम्मत माना जाया और भूमि होने के कारण केंद्र या राज्य सरकार से सम्मानित किया गया। यहां गौरतलब है कि देश के लिए वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। बैंगलुरु के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) को न तो विज्ञान सम्मत माना जाया और न ही गणपति भूमि को अशिक्षित होने के कारण केंद्र या राज्य सरकार से सम्मानित किया गया। यह व्यवहार प्रतिभा का अनादर है। यहां गौरतलब है कि 1930 में जब देश में फिरांगी हुक्मसूत्र थी, तब देश म

महामंत्री प्रत्याशी हरीश अरोरा ने किया चुनाव प्रचार



रुद्रपुर (उद संवाददाता)। रुद्रपुर व्यापारियों से रुबरु होते हुए महामंत्री व्यापार मंडल के चुनाव में महामंत्री पद के प्रत्याशी हरीश अरोरा ने आज के उम्मीदवार हरीश अरोरा ने आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील की। काशीपुर बैडपास रोड क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ना तो वह मुकदमा से डरे हैं और ना ही जेल जाने से भी पीछे हटे हैं। जनसंपर्क के दौरान हरीश अरोरा के साथ व्यापारी नेता राजेश कामरा, समाजसेवी सुखील गाबा, राजेंद्र बांगा, सौरभ राज

बेडु, मनीष गगनेजा, गगन दुनेजा, आशीष अरोरा बंटी, आशीष ग्रोवर आश, आशीष मिठा, निशांत शाही, सागर छाबड़ा, केतन गुलानी, साहिल अरोड़ा, राहुल सिंधल, गौरव, सनी नरुला, रोहित जग्गा, दीपक मित्तल, आशीर बाला, केशव ढोंगरा, अंकुश अरोरा, वंश, मुकेश मल्लिक, विक्रम खना, हिमांशु सुखीजा सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद थे।

!! व्यापार मंडल जिन्दाबाद !! !! व्यापारी एकता जिन्दाबाद !! !! व्यापार मंडल जिन्दाबाद !!

रुद्रपुर प्रान्तीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव में
आपके अमूल्य मत, सहयोग एवं
आशीर्वाद का आकांक्षी

कौषाध्यदा

संघर्ष शील कर्मठ, शिक्षित व ईमानदार
 VOTE युवा प्रत्याशी
आपका अपना
सन्दीप कुमार (सन्दीप राव)
मोबाइल नम्बर :- 9837815903

व्यापारियों के हितों में 96 दिनों तक जेल में रहे
व्यापारियों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले

रुद्रपुर प्रान्तीय उद्योग व्यापार मंडल
व्यापार मंडल
 VOTE चुनाव में

महामंत्री पद हेतु
आपका सेवक

हरीश अरोरा
मो 9837062253, 9897062253

संदीप राव ने बाजार में किया धुंआधार प्रचार



रुद्रपुर (उद संवाददाता)। व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष प्रत्याशी संदीप राव ने अंतिम दिन धुंआधार प्रचार कर व्यापारियों से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। अपने तमाम समर्थकों के साथ बाजार की विभिन्न गलियों में जनसंपर्क के दौरान व्यापारियों ने संदीप राव का फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें विजयी बनाने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ अग्रबंधुओं ने भी संदीप राव के प्रचार में ताकत झोंकते हुए व्यापारियों से संपर्क कर संदीप राव को विजयी बनाने की अपील की। बाजार में प्रभाव रखने वाले कई समाजसेवियों के साथ जनसंपर्क के दौरान संदीप राव ने व्यापारियों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यापारियों का भरपूर प्यार और स्नेह मिल रहा है जिससे उनकी जीत तय है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहे हैं। व्यापारियों के आशीर्वाद से वह चुनाव में विजयी हुए तो हर व्यापारी को साथ लेकर समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापारियों की आवाज को बुलांद करेंगे। उन्होंने सभी व्यापारियों से कल चार फरवरी को अपने पक्ष में मतदान की अपील की।

SAMSUNG **DAIKIN** **SONY** **BOSCH** **dyson**
IFB **DELL** **Haier** **JBL** **MITSUBISHI ELECTRIC**
Whirlpool **AMSTRAD** **VOLTAS** **SANSUI**

गुरु मा

महा इलेक्ट्रॉनिक उत्सव
सबसे कम दाम
की गारंटी
सबसे ज्यादा 22% तक कैशबैक

अब मिलेगा
Online
से भी सदा



GURU MAA ELECTRONICS

RUDRAPUR | 9917161111-8410888888

गढ़रपुर

गुरु नानक इन्टर प्राइजेज
(9917161111) (8410888888)

काशीपुर

चीमा चौराहा • रामनगर रोड
(9927813555) (8791989500)

हल्दानी

तिकोनिया • पीलीकोठी
(9997207007) (9690256666)